DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 22 जून 2023

हिन्दुस्तान

15000 लोगों ने किए आसन

डीडीए ने 15 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 15 हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया

पुलिस के 423 का योग

जय सिंह रोड पर बने दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर में पुलिस कमिश्नर समेत 423 पुलिसकर्मियों ने योग किया।

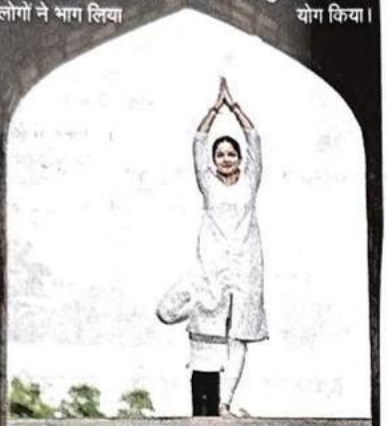

यमुना किनारे बन रहे बांस के उद्यान में LG ने किया योगाभ्यास

■ **विस, नई दिल्ली:** योग दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने योगाभ्यास किया। एलजी ने सराय काले खां के पास यमुना किनारे विकसित किए जा रहे बांस के उद्यान 'बांसेरा' में डीडीए के द्वारा आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाशीष पांडा, अथॉरिटी के मेंबर व बीजेपी विधायक ओमप्रकाश शर्मा और डीडीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की तादाद में आम लोग भी मौजूद रहे। 37 एकड़ में विकसित किए जा रहे दिल्ली के इस पहले बांस के थीम पार्क में पहली बार इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुआ।

योग फ्यूजन और डांस: अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी बदरपुर के सहयोग से कार्यक्रम किया, जिसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के रिकॉर्डिड भाषण के साथ की गई। स्टूडेंट्स ने योग फ्यूजन और डांस के जरिए योग से जोड़ने का प्रयास किया।

स्कूलों में ध्यान: रोहिणी के वीएसपीके इंटरनैशनल स्कूल में योगा प्रशिक्षक सागर मेहरोलिया ने योगाभ्यास किया। स्कूल के चेयरमैन एसके गुप्ता ने कहा कि योग के जरिए तनाव से दूर रहा जा सकता है। एमएम पब्लिक स्कूल पीतमपुरा की प्रिंसिपल रूमा पाठक ने कहा कि योग अब हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है।

'बाजार पोर्टल' लॉन्च करेगी आप सरकार, एक लाख कारोबारियों को जोड़ा जाएगा

सुविधा : दिल्ली के दुकानदार विदेश में ऑनलाइन बेच सकेंगे सामान

अच्छी खबर

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के बाजारों में मौजूद उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही 'दिल्ली बाजार पोर्टल' लॉन्च करेगी। इसके जरिए छोटे दुकानदार से लेकर व्यापारी तक अपने उत्पाद पूरी दुनिया तक बेच पाएंगे। विभिन्न बाजारों के एक लाख कारोबारियों को पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली बाजार परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि 'दिल्ली बाजार पोर्टल' से व्यापारियों को एक ऐसा मंच मिलेगा जिससे वे अपने उत्पाद वैश्विक स्तर भी बेच पाएंगे।

24 घंटे दिखाई देंगी दुकानें : दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि पोर्टल के लॉन्च होने के छह माह के अंदर ही राजधानी के एक लाख से अधिक दुकानों को पोर्टल पर लाया जाएगा। दिल्ली बाजार पोर्टल पर दुकानें डिजिटल स्टोर पर 24 घंटे दिखाई देंगी।

ई-पेमेंट की सुविधा : बैठक में पोर्टल के डिजाइन, उत्पाद कैटलॉगिंग, बाजार स्थान, जियो-टैगिंग, मैप लेआउट, ई-पेमेंट और डिजिटल लुक जैसी विशेषताओं पर बातचीत हुई। पोर्टल में दुकानों की लोकेशन और ई-पेमेंट की सुविधा मिलेगी।

तैयार होगा ई-कॉमर्स बाजार : पोर्टल के तहत व्यापारी का अपना स्टोर होगा। पोर्टल में उत्पाद सूची के माध्यम से व्यापारी अपनी दुकान और उत्पादों का प्रदर्शन कर सकेंगे। यह एक अतिरिक्त वर्चुअल स्टोर होगा जो 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन खुला रहेगा और विक्रेताओं को बड़े बाजारों में नए ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करेगा।

ये चार महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए

क्लाउड किचन के लिए एक पोर्टल पर मिलेंगे सभी लाइसेंस

दिल्ली सरकार जल्द राजधानी में क्लाउड किचन योजना लाने जा रही है। इससे करीब 20 हजार क्लाउड किचन और वहां काम करने वाले चार लाख लोगों को लाभ मिलेगा। क्लाउड किचन को कानूनी रूप दिया जाएगा। इसके तहत क्लाउड किचन के लाइसेंस के लिए एक ही पोर्टल तैयार होगा। उसी से सभी अलग-अलग विभागों से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में स्वतंत्र खाद्य दुकान (क्लाउड किचन) के संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ है कि सरकार योजना बनाने के लिए दिल्लीवालों और क्लाउड किचन से जुड़े व्यापारियों से सुझाव लेगी। दिल्ली में ज्यादातर क्लाउड किचन ग्रामीण आबादी क्षेत्र या व्यवसायिक संपत्तियों में है। वह ऑनलाइन माध्यम से खाना बेचते हैं।

सिंगापुर की तरह चांदनी चौक, मजनूं का टीला में फूड हब बनेंगे

दिल्ली सरकार राजधानी में सिंगापुर की तर्ज पर फूड हब का पुनर्विकास करेगी। इसके तहत दिल्ली के मशहूर व्यंजनों की ब्राडिंग की जाएगी। सरकार ने पहले चरण में दो फूड हब मजनूं का टीला और चांदनी चौक को विकसित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में 6 सप्ताह में योजना और पुनर्विकास के लिए डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए है। केजरीवाल ने कहा कि फूड हब पुनर्विकास में दिल्ली के पकवान को नई पहचान दी जाएगी। इसमें स्ट्रीट फूड, तिब्बती मोमोज से लेकर लजीज गोल गप्पे, विश्व प्रसिद्ध दाल मखनी, बेस्ट बटर चिकन या सभी के पसंदीदा छोले भटूरे और पराठे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के फूड हब सांस्कृतिक का ऐतिहासिक महत्व है।

औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास से छह लाख नौकरियां पैदा होंगी

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 26 गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि इस कदम से इन क्षेत्रों में छह लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन का सीमांकन करना डीडीए की जिम्मेदारी है, लेकिन जब दिल्ली में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हुआ था, लेकिन कई आवासीय और अनधिकृत इलाकों में भी छोटे-छोटे उद्योग चलने लगे। इससे अवैध और गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र बनते चले गए। दिल्ली में कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं, जहां 70 फीसदी से ज्यादा जमीन पर औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं।

चांदनी चौक की तर्ज पर विकसित होगा गांधी नगर कपड़ा बाजार

एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार गांधी नगर को चांदनी चौक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गांधी नगर को गारमेंट हब के रूप में विकसित करने को लेकर उद्योग विभाग के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द सलाहकार नियुक्त करके छह माह में बाजार का डिजाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। इसे विकसित करने पर सरकार 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केजरीवाल ने कहा कि गांधी नगर कपड़ा मार्केट पूरे विश्व में मशहूर है। गांधी नगर का पुनर्विकास परियोजना हमारे लिए सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जो दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने और हजारों की संख्या में रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times DATED----------

{ INTERNATIONAL DAY OF YOGA }

Leaders, locals perform yoga in Capital to mark occasion

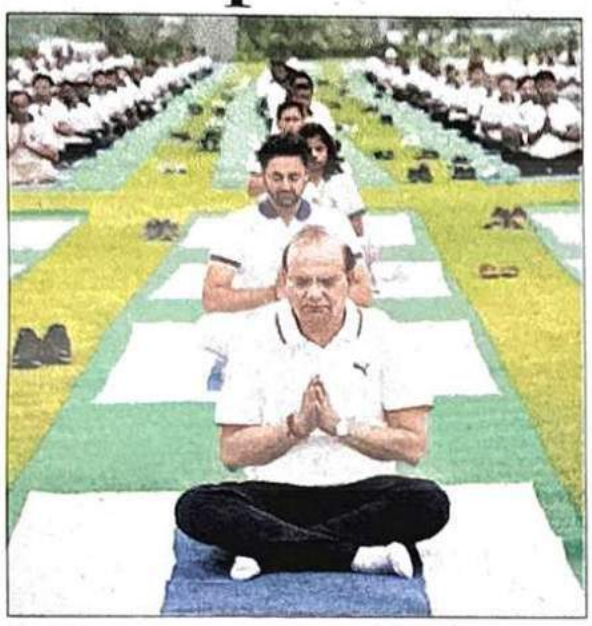

LG VK Saxena practices yoga at Baansera sports complex; people participate in a yoga event at Kartavya Path held to mark the International Day of Yoga, in Delhi on Wednesday. ARVIND YADAV/HT PHOTO

Aheli Das
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Thousands of people gathered at lawns, gardens, and auditoriums across the national capital on Wednesday morning to take part in the International Day of Yoga celebrations held at multiple prominent locations across the city, including Kartavya Path, Red Fort, Lodhi Gardens and Nehru Park.

The New Delhi Municipal Committee (NDMC), which organised the event at the Kartavya Path lawns, also organised yoga events at seven other prominent locations. The celebrations began as early as 5am.

This was also the first time that yoga day was celebrated at Kartavya Path after it was redeveloped last year.

The other locations where it was celebrated by the NDMC included Nehru Park, Lodhi Garden, Talkatora Garden, New Moti Bagh, Sanjay Jheel, Singapore Park, and Central Park in Connaught Place. The events were held in association with organisations like Patanjali Yoga Samiti, Art of Living, and Bhartiya Yog Sanstha, among others.

The theme for this year's yoga day was "Yoga for Vasudhaiva Kutumbakam" which translates to One Earth, One Family, and One Future and aims towards a better global future, peace, and unity.

While lieutenant governor VK Saxena celebrated Yoga Day at the Delhi Development Authority's Baansera sports complex at the Yamuna floodplains, chief minister Arvind Kejriwal gave yoga day a miss altogether.

Kejriwal on Tuesday tweeted about the closure of free yoga classes last year due to the alleged termination of funds by the LG.

"Yoga day for me will be the day when I will again start free yoga classes for my Delhiites," Kejriwal tweeted in Hindi.

The DDA said it organised events at 15 sports complexes with over 1,500 people taking part. Yoga day celebrations by the Delhi Police were led by Sanjay Kumar, the Special Commissioner of Police, with a total of 423 officers along with other police personnel performing yoga on the lawns of the Delhi Police Headquarters.

In a statement, the Municipal Corporation of Delhi (MCD) also said it held a series of events in all its zones, with yoga asanas like Trikanasan, Shashankasan, Dandasan, Vjrasan, Bhujangasan, Makrasan, Setubandahasan, Shavasan, and Pranayam being taught to the participants.

Several senior leaders of Delhi Bharatiya Janata Party (BJP), including Delhi BJP president Virendra Sachdeva, participated in programmes organised in the 70 assembly constituencies and across various social organisations.

Responding to Kejriwal's tweet, Sachdeva in a statement said, "The Kejriwal government first disputed the free yoga classes in Delhi, and is now not appointing yoga teachers in Delhi schools".

Facelift for food mkts, draft of cloud kitchen policy finalised

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: In a bid to support independent food outlets and generate more employment opportunities in the sector, the Delhi government will bring out a cloud kitchen policy under which all licences will be brought under a single-window system through a digital platform. In another decision, the government said it will also undertake redevelopment of various food hubs in the city, including those in Chandni Chowk and Majnu ka Tila.

A government official said the policy is likely to help the Capital's 20,000-odd such outlets and the people they employ. It will also enhance Delhi's economy and create new employment opportunities, chief minister Arvind Kejriwal said during a high-level review meeting on Wednesday.

Besides simplifying the licence process, cloud kitchens will be allowed to operate in commercial areas, and can operate round-the-clock. For kitchens smaller than 250 square feet, no fire NOC will be require. In order to keep a check on spaces, the policy says that inspection will be conducted with the help of computers. The government will also train people engaged in cloud kitchens. For financial aid, a state-level banking committee will be established for such businesses, said an official.

"The policy aims to streamline licencing procedures for cloud kitchens by implementing a user-friendly single-window system through a digital platform. This ground-breaking initiative is designed to support independent food outlets, fostering the creation of numerous employment opportunities... It is part of the government plans to empower local businesses and promote job growth," an official said.

At present, the operators apply for licences from various government organisations such as MCD, police, fire department, and DDA.

The date of the release of the policy is not final. However, the government will soon invite feedback from all stakeholders, an official said.

According to government estimates, there are around 20,000 cloud kitchens in the city.

In another decision, the government has planned to develop the Capital's popular food outlets to improve consumers' experience, and the focus of the development plan will be on food safety and hygiene, drawing inspiration from the renowned food culture of Singapore, the CM said.

An official aware of the development said the redevelopment plans include improving fundamental infrastructure such as roads, sewage systems, lighting, and parking. The goal is to develop a distinct brand for these historically and culturally significant food centres in Delhi, the official said.

Initially, Chandini Chowk and Majnu Ka Tila will be taken up for the project. Majnu Ka Tila is a hub for Asian cuisines, especially Tibetan. Similarly, Chandni Chowk is renowned for its north Indian and Mughlai food options, besides desserts.

"The transformation of Delhi's food outlets into Singapore-inspired culinary destinations is expected to create a thriving ecosystem that fosters innovation, excellence, and unparalleled dining experiences. By placing a special emphasis on food safety and hygiene, the government aims to instil consumer confidence and elevate Delhi's reputation as a culinary hotspot," Delhi government said in a statement.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 जून, 2023 -DATED----------

26 अनियमित औद्योगिक क्षेत्र जल्द किए जाएंगे नियमित

पुनर्विकास को लेकर सीएम ने की बैठक, योजना पर अब तेजी से काम होगा

- अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों में ले-आउट प्लान बनाने का 90 प्रतिशत खर्च सरकार उठाएगी
- नियमित क्षेत्र घोषित होने से औद्योगिक इकाइयों को ऋण लेने में आसानी होगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: कुछ वर्षों से लटकी 26 अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास करने की योजना पर अब तेजी से काम होगा। सरकार का दावा है कि इससे लगभग छह लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना की समीक्षा की। पुनर्विकास कार्य के बाद इन्हें नियमित घोषित किया जाएगा। इससे औद्योगिक इकाइयों को ऋण लेने में आसानी होगी।

अरविंद केजरीवाल • जागरण आर्काइव

सीएम ने कहा कि अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों में ले-आउट प्लान बनाने का 90 प्रतिशत खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। केवल 10 प्रतिशत हिस्सा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से लिया जाएगा, ताकि इंडस्ट्री की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। इसे विश्वस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रों में बदला जाएगा। इस दौरान उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने समय पर नियमित औद्योगिक क्लस्टर नहीं बनाए, जिससे अवैध या अनियमित औद्योगिक एरिया बनते गए। शहर के कई इलाकों में उद्यमियों को व्यवसाय और कारखाना चालू रखने के लिए आवासीय जमीन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

क्या होता है अनियमित औद्योगिक क्षेत्र

दिल्ली में ऐसे कई रिहायशी क्षेत्र हैं, जहां की 70 प्रतिशत से ज्यादा जमीन पर उद्योग चल रहे हैं। इन्हें अनियमित औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ये सभी औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। इनके नियमित औद्योगिक जोन बनने से असुरक्षा की भावना भी खत्म हो जाएगी।

तीन चरण में होगा पुनर्विकास

ले-आउट तैयार करना और स्वीकृति : दिल्ली सरकार मास्टर प्लान-2041 की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ले-आउट योजना तैयार करेगी। ले-आउट योजना स्थानीय उद्योग एसोसिएशन या सोसायटी के साथ साझेदारी में तैयार किया जाएगा।

बुनियादी ढांचे का पुनर्विकास : औद्योगिक क्षेत्रों को हरा-भरा, स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। सीवेज, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था और सड़कों को बेहतर किया जाएगा। बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए डेवलपर्स को शामिल किया जाएगा।

कामन फैसिलिटी सेंटर्स का निर्माण : औद्योगिक क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से एक्सपीरियंस सेंटर, टूल रूम, प्रोसेसिंग सेंटर, अनुसंधान एवं विकास, मान्यता प्राप्त टेस्ट लैब, ट्रेनिंग सेंटर, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, कच्चा माल बैंक और लाजिस्टिक सेंटर समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इन अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों का होगा पुनर्विकास

आनंद पर्वत, शाहदरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, हस्तसाल पाकेट-ए, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ी गांव, ख्याला, हस्तसाल पाकेट-डी, शालीमार गांव, न्यू मंडोली, नवादा, रिठाला, स्वर्ण पार्क मुंडका, हैदरपुर, करावल नगर, डाबरी, बसई दारापुर, प्रह्लादपुर बांगर, मुंडका उद्योग नगर दक्षिण, फिरनी रोड मुंडका, रणहोला, नगली सकरावती व टीकरी कला।

संबंधित खबरें >> जागरण सिटी

क्लाउड किचन के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी कार्ययोजना

- योजना के श्वेतपत्र को दी मंजूरी, एक ही पोर्टल पर सारे लाइसेंस
- पैदा होंगे रोजगार के अवसर, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार बहुत जल्द राजधानी में क्लाउड किचन को लेकर कार्ययोजना बनाने जा रही है। इससे दिल्ली में चल रहे लगभग 20 हजार क्लाउड किचन और वहां काम करने वाले चार लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में इंडिपेंडेंट फूड आउटलेट (क्लाउड किचन) के संचालन को लेकर चल रहे पहलों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने योजना के श्वेतपत्र को मंजूरी भी दी। कार्ययोजना को अंतिम रूप देने से पहले जनता और क्लाउड किचन से जुड़े लोगों के सुझाव लेंगी। इसके बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बैठक में सीएम ने कहा कि क्लाउड किचन को लेकर सरकार इसलिए कार्ययोजना बना रही है, ताकि इस क्षेत्र में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हो सकें। योजना के धरातल पर आने से दिल्ली में क्लाउड किचन को कानूनी रूप दिया जाएगा। इससे किचन संचालित करने वाले व बिजनेस शुरू करने वाले दिल्ली सरकार के एक ही पोर्टल पर अलग-अलग विभाग के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीएम ने कहा, इस नीति के आने से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज व विभिन्न विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद थे।

बता दें कि जो व्यापारी इन क्लाउड किचन संचालित करते हैं, उन्हें सरकार की अलग-अलग संस्थाओं एमसीडी, पुलिस, फायर, डीडीए में लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में व्यापारियों को कई सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि यह एक नई पहल है और इस विषय में सरकार की अब तक कोई ठोस योजना या नीति अब तक नहीं थी। लेकिन, अब सरकार इस पहल को कानूनी रूप देने को तैयार है।

विकसित होंगे फूड आउटलेट

दिल्ली सरकार सिंगापुर की तर्ज पर फूड हब बाजार का पुनर्विकास कर रही है। इसके तहत दिल्ली के फूड हब की ब्राडिंग की जाएगी। पहले चरण में दो फूड हब मजनू का टीला और चांदनी चौक की ब्राडिंग की जाएगी। इसकी डिजाइन तैयार की जा रही है। ये बाजार पहले से ही स्वादिष्ट व्यंजन के लिए जाने जाते हैं। अब सरकार इन्हें और बेहतर बनाने जा रही है। यहां फूड सेफ्टी की गाइड लाइंस और साफ-सफाई का पूरा पालन कराया जाएगा। इसके लिए सरकार एक प्रतियोगिता भी कराएगी जिसमें सभी आर्किटेक्ट अपनी बनाई डिजाइन जमा करेंगे। सबसे अच्छी डिजाइल पेश करने वाले आर्किटेक्ट को इन प्रसिद्ध बाजार को डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि फूड हब पुनर्विकास में दिल्ली के पकवान को नई पहचान दी जाएगी। उसमें स्ट्रीट फूड, तिब्बती मोमोज से लेकर गोल गप्पे, विश्व प्रसिद्ध दाल मखनी, बेस्ट बटर चिकन या सभी के पसंदीदा छोले भटूरे और पराठे शामिल होंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, JUNE 22, 2023

NAME OF NEWSPAPERS---------- ----------DATED----------

In fitness of things, Delhi flexes muscles

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena stretched his muscles at Baansera on the bank of river Yamuna at the 9th International Day of Yoga function organised on Wednesday by Delhi Development Authority. The event began with a recorded address by Prime Minister Narendra Modi. DDA celebrated the day at its various sports complexes and parks.

After the event at Baansera, the LG inspected the newly developed park and appreciated the work done for its development in a short time. He suggested planting more trees and asked DD to give special attention to keeping the surroundings clean.

DDA also celebrated Yoga Day at the sports complexes in Siri Fort, Saket, Vasant Kunj, Hari Nagar, Paschim Vihar, Dwarka, Chilla and Rohini and at the Major Dhyan Chand Sports Complex, Netaji Sports Complex, Rashtriya Swabhiman Khel Parisar, Poorv Delhi Khel Parisar, Yamuna Sports Complex, Squash & Badminton Stadium and the Commonwealth Games Village Sports Complex. Over 15,000 people participated in the event at these sports complexes, claimed DDA officials.

Around 10,000 people went through asana's at New Delhi Municipal Council's yoga day celebrations at Nehru Park, Lodhi Garden, Talkatora Garden, Kartavya Path, Singapore Park, New Moti Bagh residential complex, Sanjay Jheel in Lakshmibai Nagar and Central Park in Connaught Place. The NDMC events were organised in collaboration with Art of Living, Patanjali Yoga Samiti, Gayatri Parivar, Morarji Desai National Institute of Yoga, Isha Yoga Centre, The Yoga Institute, Akhil Bhartiya Yoga Shikshak Mahasangh and Bharatiya Yog Sansthan.

Rajesh Mehta & Sanjeev Rastogi

LODHI GARDEN

KARTAVYA PATH

The Municipal Corporation of Delhi similarly organised yoga events in which its deputy commissioners, councillors, officials and employees performed yogic asana alongside schoolchildren. Students with disabilities from MCD schools also participated with great enthusiasm, performing trikanasana, shashankasana, dandasana, vajrasana, bhujangasana, makrasana, setubandahasana, shavasana and Pranayam.

Chief minister Arvind Kejriwal tweeted about the occasion saying, "Two years ago, Delhi government started free yoga classes for Delhi's people and around 17,000 people started doing yoga every day. Last year the yoga classes were stopped. People became very sad. Should public welfare programmes like this be stopped? Yoga day for me will be the day when I can again start free yoga classes for my Delhiites."

In Malviya Nagar, Delhi Jal Board vice-chairman and Malviya Nagar MLA Somnath Bharti participated in a yoga event with RWA representatives, residents and children. The locals participating in the yoga session with Bharti demanded the resumption of Delhi government's free yoga classes.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, JUNE 22, 2023 ----------DATED----------

Markets to go online, cloud kitchen policy soon

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The markets in Delhi will soon get a digital platform to reach out to customers not only across the country but also globally with the launch of Dilli Bazaar e-portal. It will feature 10,000 vendors in its initial phase, Delhi government said on Wednesday.

Claiming it to be the first such portal in the country, the government said it was in the final stages of launching the platform. On Wednesday, chief minister Arvind Kejriwal chaired a high-level review meeting to assess the progress of the project.

The government also plans to bring in a cloud kitchen policy soon, under which all licences will be brought under a single-window system through a digital platform. "The scheme is being brought in to support independent food outlets so that they can generate more employment opportunities," said Kejriwal.

According to Delhi government, "Dilli Bazaar is to be an open network for digital commerce, giving buyers options to choose as per their liking. With zero setup cost, products on Dilli Bazaar will be significantly cheaper than those on e-commerce portals." The government aims to bring over one lakh shops in Delhi on the portal, offering them a 24x7 digital store front within six months of its launch. All shopkeepers in Delhi will be allowed to register on the portal.

KEJRIWAL SAYS

The scheme is being brought in to support independent food outlets so that they can generate more employment opportunities

Emphasising the "Go Local" motto, customers on this platform will be able to search for products, markets, sellers and geographical areas to discover the unique markets of Delhi, the statement added. The portal is expected to give a significant boost to the renowned local shops in various city markets, offering search options by market, shop name and product category.

The cloud kitchen policy is likely to help Delhi's 20,000 such establishments and lakhs of workers employed in it, said Kejriwal. The policy would incorporate suggestions from citizens and entrepreneurs and the government would also float a white paper on it in public domain, he added.

According to an official, "Operators and entrepreneurs running cloud kitchens will no longer have to face the hassle of obtaining licences from various government departments. They will be able to apply for licences through a single portal provided by Delhi government."

A cloud kitchen utilises a commercial setup to prepare food that's distributed through delivery apps. Their operators have to apply for licences from various government organisations such as municipal corporation, police, fire department and Delhi Development Authority. However, the government doesn't so far have any concrete policy for such establishments, the official added.

Once the policy is formulated, cloud kitchens will be operational in commercial areas for 24 hours and can operate without a no-objection certificate from the fire department for spaces less than 250 square feet, the government stated.

DDA set to increase conversion charges

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi Development Authority (DDA) is set to increase charges for conversion of land from leasehold to freehold for commercial and industrial properties as well as multilevel parking in the city.

In its last meeting, held on June 14, the authority gave approval to hike the rates for FY 2023-24 by 10% on last year's rates.

"While we can implement the decision on a provisional basis, a proposal will be sent to the ministry of housing and urban affairs for final approval and notification, which is expected soon. The conversion rate is 6% of the land value and the increase will be 10% of this value," said the official.

In the case of commercial properties, the land rates for calculating conversion charges have been proposed to increase from Rs 1,98,504 per sqm to Rs 2,18,354 per sqm for the Central, South and Dwarka zones. For the West, North, East and Rohini areas, the rates are expected to go up from Rs 1,37,855 per sqm to Rs 151,640 per sqm. For Narela, they are set to be hiked from Rs 55,144 per sqm to 60,658 per sqm.

In the case of industrial properties, the leasehold-freehold conversion charges in Central, South and Dwarka zones, have been proposed to increase from Rs 1,19,106 per sqm to Rs 1,31,016. For the West, North, East and Rohini areas, they will increase from Rs 82,715 per sqm to Rs 90,986 per sqm. In Narela, the rate will be hiked from Rs 41,359 per sqm to Rs 45,494 per sqm.

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 जून, 2023

- दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा व विशेष आयुक्त संजय कुमार ने योग किया।
- केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विज्ञान भवन में केंद्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ योग किया
- महापौर डा. शैली ओबेराय, उपमहापौर आले इकबाल आदि ने सुभाष नगर सामुदायिक केंद्र में योग किया।
- एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय नेहरू पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
- दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनाट प्लेस में योग किया।
- डीडीए के पार्कों और खेल परिसर में योग कार्यक्रम हुए, डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशीष पंडा भी शामिल हुए।
- गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने गांधी दर्शन, राजघाट में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
- चांदनी चौक के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. हर्षवर्धन ने मेजर ध्यान चंद खेल परिसर में योग कार्यक्रम में भाग लिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | JUNE 22, 2023

DDA celebrates Yoga Day for overall wellness

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Development Authority (DDA) on Wednesday celebrated the 9th International Day of Yoga at its sports complexes and parks, promoting the manifold benefits of this ancient practice. The Lieutenant Governor of Delhi and Chairman of DDA VK Saxena led a captivating yoga session at Baansera, a scenic location nestled along the banks of the Yamuna River.

Joining him were Subhasish Panda, Vice Chairman of DDA, and OP Sharma, Authority Member and MLA of Vishwas Nagar, adding to the event's grandeur. Baansera, sprawling across 37 acres, is Delhi's first Bamboo Theme Park, serving as a perfect backdrop for the occasion.

The festivities commenced with a recorded address by Prime Minister Narendra Modi, setting the tone for the International Yoga Day celebrations. This year's theme, "Yoga For Vasudaiva Kutumbakam," emphasized the unity of humanity and our collective responsibility towards the planet. The United Nations General Assembly proclaimed June 21 as the International Day of Yoga on December 11, 2014, responding to Prime Minister Narendra Modi's appeal during his speech on September 27, 2014

DDA's commitment to spreading awareness about yoga extended beyond Baansera. The organization organized Yoga Day events at 15 sports complexes across Delhi, including prominent venues such as Siri Fort Sports Complex, Saket Sports Complex, Netaji Sports Complex, Vasant Kunj Sports Complex, and more.

Delhi Lt Governor VK Saxena performs yoga on the International Day of Yoga, at Sarai Kale Khan in New Delhi on Wednesday Ranjan Dimri | Pioneer

These engaging activities witnessed an overwhelming participation of over 15,000 individuals, showcasing the growing popularity of yoga in the city. Following the Yoga Day celebration at Baansera, the Lieutenant Governor expressed his appreciation for the remarkable development of the newly created park in a short period.

Saxena emphasised the importance of green spaces and urged authorities to focus on the cleanliness and maintenance of the surroundings. In addition to the sports complexes, the International Day of Yoga was commemorated at prominent locations such as Coronation Park in Burari, SwarnJayanti Park in Rohini, and CBD Ground in Karkardooma. These venues collectively attracted over 6,500 participants, highlighting the widespread enthusiasm for yoga across Delhi. Prominent Members of Parliament also actively participated in the Yoga Day celebrations. Ramesh Bidhuri, MP from South Delhi, engaged in yoga activities at Vasant Kunj Sports Complex, while Dr Harsh Vardhan, MP from Chandni Chowk, joined the event at Major Dhyan Chand Sports Complex. Hans Raj Hans, MP from North West Delhi, graced the occasion at SwarnJayanti Park Rohini, and Vijender Gupta, Authority Member and MLA of Rohini, actively participated in the Yoga event at Rohini Sports Complex.

DDA's annual celebration of the International Day of Yoga demonstrates its commitment to promoting overall health, wellness, and happiness among individuals, communities, and organizations. By organizing public yoga sessions, workshops, and meditation gatherings led by expert trainers, DDA aims to foster a sense of unity, inspire a "Fit India" movement, and encourage the adoption of yoga as an essential tool for well-being.

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 22 जून • 2023

बांसेरा पार्क में एलजी के साथ दिल्ली के लोगों ने किया योगा

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

■ योगासन से पहले लोगों ने सुना प्रधानमंत्री का रिकार्डेड संबोधन

उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा ने बुधवार को सराय काले खां के सामने यमुना के किनारे बांसेरा में योगासन किया। इस कार्यक्रम में डीडीए बोर्ड के सदस्य ओपी शर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। योग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकार्डेड संबोधन सुनाया गया। 9वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय 'योग फॉर वसुधैव कुटुम्बकम' रखा गया था। डीडीए की तरफ से सभी 15 खेल परिसरों में योगासन कराया गया। खेल परिसरों में करीब 15 हजार लोगों ने एकत्र होकर योगासन किया।

योगासन संपन्न होने के बाद एलजी से नवविकसित बांसेरा पार्क का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चल रहे कार्य की सराहना करते हुए और अधिक पेड़ उगाने का सुझाव दिया। उप-राज्यपाल ने प्राधिकरण कार्यालयों के आसपास सफाई व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए सफाई व्यवस्था जरूरी है। डीडीए के सिरी फोर्ट खेल परिसर, साकेत खेल परिसर, नेताजी खेल परिसर, वसंत कुंज खेल परिसर, हरिनगर खेल परिसर, पश्चिम विहार खेल परिसर, द्वारका खेल परिसर, मेजर ध्यान चंद खेल परिसर, रोहिणी खेल परिसर, राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, चिल्ला खेल परिसर, यमुना खेल परिसर, स्कवैश एण्ड बैडमिंटन स्टेडियम और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज खेल परिसर में हजारों लोगों ने योगासन किया। डीडीए का कहना है कि बुराड़ी स्थित कोरोनेशन पार्क, रोहिणी स्थित जयंती पार्क, कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में आयोजित योग कार्यक्रम में 6,500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS
नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 22 जून • 2023
राष्ट्रीय सहारा

26 नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली (एसएनबी)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार राजधानी के सभी 26 नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास करेगी। इससे छह लाख रोजगार पैदा होंगे। पुनर्विकास के लिए ले-आउट प्लान तैयार कराएगी। ले-आउट प्लान बनाने पर होने वाले खर्च का 90 फीसद हिस्सा सरकार वहन करेगी। पुनर्विकास की योजना बनाने से पहले औद्योगिक एसोसिएशनों को हर संभव मदद देंगे। यह जानकारी उन्होंने औद्योगिक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सभी 26 नॉन कंफर्मिंग क्षेत्रों का पुनर्विकास कर औद्योगिक क्षेत्र में बदला जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मास्टर प्लान के मुताबिक आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन का सीमांकन करना दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जिम्मेदारी है, लेकिन डीडीए ने इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। जरूरत के मुताबिक दिल्ली में आवासीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण ही अनधिकृत कालोनियां पनपने लगीं। दिल्ली में जमीन का इस्तेमाल मास्टर प्लान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा। मौजूदा समय में दिल्ली में कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं, जहां 70 फीसद से अधिक जमीन पर औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 26 ऐसे नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र हैं। इन नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा तबका नौकरी करता है। यह सभी औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हैं। पुनर्विकास से जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं सरकार को भी राजस्व मिलेगा।

मुख्यमंत्री का दावा, छह लाख नए लोगों को मिलेगा रोजगार

सरकार बनाएगी ले-आउट प्लान

ले-आउट प्लान पर होने वाले खर्च का 90 फीसद वहन करेगी सरकार : केजरीवाल

सीएम का आरोप, डीडीए ने नहीं निभाई ठीक से जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र में पानी, बिजली, अपशिष्ट उपचार, आग लगने की घटनाएं रोकने के लिए जरूरत के मुताबिक योजना नहीं बनाई गई हैं। ऐसे औद्योगिक इलाकों में उद्यमियों के पास पर्याप्त दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं होते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 51 हजार यूनिट चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉन कंफर्मिंग क्षेत्र पुनर्विकसित होने के बाद उद्यमियों को बैंक लोन आदि मिलने में आसानी होगी। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इन नॉन कंफर्मिंग एरिया का तीन चरणों में पुनर्विकास किया जाएगा।

,सीएम ने घोषणा की कि मास्टर प्लान-2041 का ध्यान रखते हुए ले-आउट तैयार करना, उन्हें स्वीकृत करना सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने पुनर्विकास योजना में आनंद पर्वत, शाहदरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, हस्तसाल पॉकेट-ए, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ी गांव, ख्याला, हस्तसाल पॉकेट-डी, शालीमार गांव, न्यू मंडोली, नवादा, रिठाला, स्वर्ण पार्क मुंडका, हैदरपुर, करावल नगर, डाबरी, बसई दारापुर, प्रलिादपुर बांगर, मुंडका उद्योग नगर दक्षिण, फिरनी रोड मुंडका, रणहोला, नंगली सकरावती, टिकरी कलां को शामिल किया है।

सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या गलत बोल रहे सीएम : बिधूड़ी

■ **नई दिल्ली (एसएनबी)।**

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उनके शिक्षामंत्री के दावे को झूठ बताते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने के बाद से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है।

बिधूड़ी ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा है कि वर्ष 2013-14 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 16.1 लाख थी। इसके विपरीत आज दस साल बाद यानी 2023-24 में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 15,42,629 है। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार बनने से पहले सरकारी स्कूलों में हर साल 60 हजार छात्रों की संख्या बढ़ रही थी। इस झूठ के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने बयान जारी कर कहा कि निजी स्कूलों से निकलकर चार लाख बच्चें के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की बाते कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया एवं मौजूदा शिक्षा मंत्री आतिशी लगातार झूठें दावे करती रही हैं। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि आतिशी ने अपने ब्रिटेन दौरे के समय भी यही झूठा दावा किया है। मुख्यमंत्री बताएं वह चार लाख बच्चे कहां हैं। सरकारी आंकड़ों का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने दस साल के आंकड़े सामने रखे। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बच्चों की मौजूदा संख्या में भी सरकार फर्जीबाड़ा कर रही है।

■ **ब्रिटेन यात्रा के दौरान शिक्षामंत्री ने गलत आंकड़े रखे : नेता प्रतिपक्ष**

■ **केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी पर लगाया झूठे दावे करने का आरोप**

पिछले 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या

2013-14 में	16.1 लाख
2014-15 में	15.4 लाख
2015-16 में	15.1 लाख
2016-17 में	15.3 लाख
2017-18 में	14.6 लाख
2018-19 में	14.9 लाख
2019-20 में	15.1 लाख
2023-24 में	15.4 लाख

आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2017-18 में सरकारी स्कूलों में 14,56,313 बच्चे थे, लेकिन इसमें 5,67,816 बच्चे गैरहाजिर रहे। असलियत यह है कि केजरीवाल की सरकार बनने से पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 70 फीसद थी, जो अब 60 फीसद ही रह गई है।

बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 500 नए स्कूल खोलने का दावा किया था, लेकिन असलियत इसके उलट है। नए स्कूल खुलने की बजाए 50 स्कूल बंद हो गए, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली सरकार को 13 स्कूलों के लिए जमीन दी है। नेशनल परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में दिल्ली 8वें नंबर पर है। स्थिति यह है कि 700 स्कूलों में कक्षा-11-12 में साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। 12वीं क्लास के नतीजों में इस साल दिल्ली चौथे एवं छठे स्थान पर रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला | नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 22 जून 2023

26 औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, 6 लाख को रोजगार

ले आउट प्लान का 90% खर्च सरकार उठाएगी, इंडस्ट्री की भी होगी भागीदारी, नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र को कन्फर्मिंग घोषित करेगी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में 26 नये औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। केजरीवाल सरकार नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास कर युवाओं के लिए करीब छह लाख नौकरियां पैदा करेगी। इनके ले-आउट प्लान का 90 फीसदी खर्च सरकार उठाएगी, जबकि 10 फीसकी औद्योगिक इकाइयों से लेगी ताकि इंडस्ट्री की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके।

बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि नॉन कंफर्मिंग नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास कर विश्वस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रों में बदला जाएगा।

उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मास्टर प्लान के मुताबिक आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन का सीमांकन करना डीडीए की जिम्मेदारी है। लेकिन जब दिल्ली में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियों का विस्तार हुआ, उस दौरान डीडीए दिल्ली की विकास की गति के साथ नहीं चल पाया। डीडीए द्वारा समय पर नियमित इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं बनाए गए। ऐसे में अवैध या नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया बनते गए। दिल्ली में करीब 70 फीसदी से ज्यादा जमीन पर औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, जिन्हें नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है।

सांकेतिक

ये बनेंगे कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र

आनंद पर्वत, शाहदरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, हस्तसाल पॉकेट-ए, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ी गांव, ख्याला, हस्तसाल पॉकेट-डी, शालीमार गांव, न्यू मंडोली, नवादा, रिठाला, स्वर्ण पार्क मुंडका, हैदरपुर, करावल नगर, डाबरी, बसई दारापुर, प्रह्लादपुर बांगर, मुंडका उद्योग नगर दक्षिण, फिरनी रोड मुंडका, रणहोला, नंगली सकरावती, टिकरी कलां कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे।

प्रशासन की जिम्मेदारी तय होगी, भ्रष्टाचार घटेगा

नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल इलाकों में पानी, बिजली, अपशिष्ट प्रबंधन, फायर सर्विस इत्यादि से जुड़ीं तमाम सुविधाएं इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से प्लान नहीं हैं। नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में उद्यमियों के पास पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। कई बार उन्हें अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं। कोई हादसा होता है, तब विभाग उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में स्थिति का स्थाई समाधान करने के लिए केजरीवाल सरकार ने इन नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया को कंफर्म इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में इन इलाकों में 51 हजार इकाइयां चल रही हैं।

तीन चरणों में किया जाएगा पुनर्विकास

- पहले चरण में ले-आउट तैयार कर अप्रूवल मिलेगा, दिल्ली सरकार के पैनल बद्ध सलाहकारों द्वारा सेफ्टी और अपग्रेडेड फैसिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए एमपीडी-2041 की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ले-आउट योजना तैयार की जाएगी। स्थानीय उद्योग एसोसिएशन या सोसायटी से सलाह ली जाएगी।
- दूसरे चरण में बुनियादी ढांचे का पुनर्विकास किया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्रों को हरा-भरा, स्वच्छ बनाया जाएगा। सीवेज, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था और सड़कों को बेहतर किया जाएगा।
- कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का निर्माण होगा, जरूरत के हिसाब से एक्सपीरियंस सेंटर, टूल रूम, प्रोसेसिंग सेंटर, अनुसंधान एवं विकास, मान्यता प्राप्त टेस्ट लैब, ट्रेनिंग सेंटर, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, रा मेटेरियल बैंक और लॉजिस्टिक सेंटर खोले जाएंगे।

जल और थल में हुआ योग, लोगों में दिखा जोश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली जल से थल तक योगमय हुई। राजधानी में कई जगहों पर लोगों ने योग किए। डीडीए की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जबकि एनडीएमसी के कार्यक्रमों में उसके सदस्यों और अन्य नेताओं ने योग किया।

भाजपा ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में योग कार्यक्रम आयोजित किए। डीडीए के यमुना तट स्थित बांसेरा में योग कार्यक्रम उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शिरकत की, जबकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पुराना किला के आयोजन में शामिल हुई। वजीराबाद में पूर्व भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यमुना नदी के अंदर योग किया।

बांसेरा के अलावा डीडीए ने अपने 15 खेल परिसरों में भी योग दिवस मनाया। इन खेल परिसरों में 15000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं, एनडीएमसी ने आठ स्थानों पर योग दिवस मनाया, इन स्थानों पर लगभग 10000 प्रतिभागियों ने योग के सामान्य प्रोटोकॉल में भाग लेकर योगाभ्यास किया। दिल्ली छावनी बोर्ड ने नागेश गार्डन में योग कार्यक्रम का आयोजन किया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विजय मंडल पार्क, डी ब्लॉक गुलमोहर पार्क और सेंट्रल पार्क सर्वोदय एनक्लेव में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ योग अभ्यास कर योग दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती के साथ आरडब्ल्यूए, स्थानीय निवासियों और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। योग के जरिए लोगों को योग का महत्व समझाया गया और स्वस्थ रहने के लिए लोगों से जीवन में योग को स्थान देने की अपील की गई।

वजीराबाद घाट पर पानी में योग करते वाटर स्पोर्ट्स क्लब के छात्र व प्रशिक्षक। विवेक निगम

योग कार्यक्रमों में शरीक हुए भाजपाई

प्रदेश भाजपा की तरफ से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, अन्य पदाधिकारी, सांसद, विधायक, निगम पार्षद शामिल हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद प्रकाश जावड़ेकर एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा ने भगवान महावीर निवारण महोत्सव समिति द्वारा कनाट प्लेस में आयोजित योग दिवस समारोह में सम्मिलित होकर योग किया। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अलका गुर्जर एवं प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी मोलड़बंद विस्तार में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद मनोज तिवारी ने 'योगा ऑन वाटर' कार्यक्रम में किया योग।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER पंजाब केसरी DELHI ----------DATED----------

छह लाख नई नौकरियां पैदा करेगी दिल्ली सरकार: केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल ने नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के पुनर्विकास को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

26 नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों को कंफर्मिंग एरिया बनाने के लिए करेंगे पुनर्विकास

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली सरकार दिल्ली में स्थित 26 नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास करने जा रही है। इसके विकसित होने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके मद्देनजर बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 26 नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों को कंफर्मिंग एरिया बनाने के लिए सभी क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा। इससे यहां तकरीबन 6 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने बताया कि नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया में ले-आउट प्लान बनाने का 90 फीसदी खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। केवल 10 फीसदी हिस्सा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से लिया जाएगा। जिससे कि इंडस्ट्री की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद इसे कंफर्मिंग एरिया घोषित कर दिया जाएगा। इन नॉन-कंफर्मिंग नोटिफाइड इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास कर विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रों में बदला जाएगा।

दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में चल रही औद्योगिक गतिविधियां

समीक्षा बैठक के दौरान उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन का सीमांकन करना दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जिम्मेदारी है। लेकिन जब दिल्ली में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल गतिविधियों का विस्तार हुआ था, उस दौरान डीडीए दिल्ली की विकास की गति के साथ नहीं चल पाया।

पुनर्विकास से लाखों युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इन 26 नॉन-कंफर्मिंग नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए औद्योगिक एसोसिएशन की हर संभव मदद करने को हमेशा तैयार है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में दिल्ली का एक बड़ा तबका नौकरी करता है। ये सभी इंडस्ट्रीयल इलाकें दिल्ली की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हैं। इन नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास से लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी होगा।

औद्योगिक इकाइयों को लोन लेने में होगी आसानी

पहले कहा जाता था कि इन नॉन कंफर्मिंग नोटिफाइड इंडस्ट्रीयल एरिया की सोसायटी अपने इलाकों का आकलन कर पुनर्विकास योजना का पूरा खर्च उठाएगी। मगर कई साल बीतने के बाद भी नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास नहीं हुआ। अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि हम इन इंडस्ट्रीयल एरिया का ले-आउट प्लान तैयार करने के लिए कुल खर्च का 90 फीसदी हिस्सा खुद उठाएंगी।

रमेश बिधूड़ी ने किया योग

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): अंतराष्ट्रीय योग दिवस पर दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कई स्थानों पर लोगों के साथ योग दिवस मनाया। उन्होंने अपने योगाभ्यास की शुरुआत सुबह 6 बजे पालम विधानसभा के महावीर एन्क्लेव स्थित पार्क में योग कार्यक्रम में शामिल होकर की। उसके बाद साध नगर, राजापुरी, मधु विहार, वसंत कुंज व पुल प्रहलादपुर आदि स्थलों पर योगाभ्यास किया। इस दौरान रमेश बिधूड़ी ने डीडीए पार्क एमबी रोड स्थित कंटेनर यार्ड में सीआरपीएफ के जवानों के साथ भी योगाभ्यास किया। इस अवसर पर सांसद बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकृति दिलवाई। उन्होंने कहा कि योग न सिर्फ हमारे मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखने में सहायक है, बल्कि यह शरीर को कई गंभीर बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वस्थ व दीर्घायु जीवन के लिए नियमित योगाभ्यास करना चाहिए।

उपराज्यपाल ने किया बांसेरा में योगासन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डीडीए ने अपने खेल परिसरों और पार्कों में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने यमुना के तट पर स्थित बांसेरा में योगासन किया। उनके साथ डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा और प्राधिकरण सदस्य व विश्वास नगर क्षेत्र के विधायक ओपी शर्मा उपस्थित रहे। बांसेरा 37 एकड़ में फैला हुआ दिल्ली का पहला बैंबू(बांस) थीम पार्क है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रिकॉर्डेड भाषण के साथ हुई। बांसेरा के अलावा डीडीए ने अपने 15 खेलपरिसरों में योग दिवस मनाया। इनमें 15000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसके बाद एलजी ने नए विकसित पार्क का निरीक्षण किया और बहुत कम समय में इसके विकास के लिए किए गए कार्य की सराहना की।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE millenniumpost
THURSDAY, 22 JUNE, 2023 | NEW DELHI ,TED----------

Govt aims to create 6 lakh job opportunities

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The AAP-led Delhi government is set on creating 6,00,000 job opportunities through its initiatives to redevelop non-conforming industrial areas with Chief Minister Arvind Kejriwal expressing his determination to transform all 26 non-conforming industrial areas into recognised conforming industrial areas through a comprehensive redevelopment plan.

The redevelopment of the non-conforming industrial areas is crucial for the growth and progress of the industrial sector. Once the redevelopment is complete, the areas will be accorded the coveted Conforming Area status, providing a conducive environment for businesses to thrive.

The Delhi government will take on 90 per cent of the costs, with only 10 per cent of the expenses being borne by the industries. By transforming the non-conforming areas into conforming ones, the government aims to enhance the productivity and competitiveness of the industrial sector in Delhi.

Delhi to bear 90% cost to convert non-conforming industrial areas to conforming ones: CM Kejriwal

In a meeting on Wednesday Kejriwal discussed the progress made so far, identified challenges, and formulated strategies to expedite the redevelopment process. The Chief Minister expressed his confidence in the project's success and reaffirmed his commitment to the growth and prosperity of Delhi's industrial sector.

As per Delhi's Master Plan, the demarcation of land for residential, commercial, and industrial use is the responsibility of the Delhi Development Authority (DDA).

However, when the expansion of residential, commercial, and industrial activities took place in Delhi, the DDA could not keep up with the pace of development. As a result, unauthorised colonies began to emerge due to the unavailability of residential colonies. Currently, there are several residential areas in Delhi where more than 70 percent of the land is being used for industrial activities, known as non-conforming industrial areas.

The industrial areas employ a significant workforce in Delhi and constitute a substantial portion of Delhi's GDP and with the redevelopment, it will create employment opportunities for youth.

Delhi government to launch Cloud Kitchen Scheme

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi government is set to launch the Cloud Kitchen Scheme which will benefit approximately 20,000 cloud kitchens and the four lakh individuals employed in these establishments.

During the review meeting on Wednesday, the proposal and outline for the scheme were discussed which was approved by Chief Minister Arvind Kejriwal. Before finalising the scheme, the Delhi government will seek suggestions from citizens and entrepreneurs associated with cloud kitchens after which the cloud kitchen policy will be implemented.

Kejriwal said that a scheme will be introduced to regulate independent food outlets (cloud kitchens) and create sufficient employment opportunities in the sector. The implementation of the scheme will provide legal recognition to cloud kitchens operating in Delhi, eliminating the hassle of obtaining licenses from various government departments. Business owners and

Before finalising the scheme, the govt will seek suggestions from citizens and entrepreneurs associated with cloud kitchens

startups will be able to apply for all types of licenses through a single portal established by the Delhi government. The government will give legal recognition to cloud kitchens operating in the city.

Often, people order food through mobile apps like Zomato, Swiggy, or others, without realizing that such food is predominantly prepared in small-scale cloud kitchens. Those running these cloud kitchens have to apply for licenses from multiple government agencies such as MCD, Police, Fire, and DDA. However, the Delhi government is now introducing the Cloud Kitchen Scheme to provide legal recognition and simplify the lives of entrepreneurs.

YOGA DAY CELEBRATIONS

To raise awareness about the numerous benefits of yoga, Delhi Development Authority (DDA) celebrated 9th International Day of Yoga at its sports complexes and parks. Lt Governor and DDA Chairman, Vinai Kumar Saxena, performed yoga at Baansera on the bank of river Yamuna. Subhasish Panda, Vice Chairman DDA and O P Sharma, authority member and MLA Vishwas Nagar were also present at the event. Baansera is Delhi's first Bamboo Theme Park spread over 37 acres

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भास्कर
NAME OF NEWSPAPERS----------

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस • दिल्ली में कई शिविर आयोजित

एलजी बोले- योग करने में कुछ खर्च नहीं होता, सांसद ने किया 'योगा ऑन वॉटर'

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

राजधानी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कई स्थानों पर योग शिविर लगे। योग दिवस वसुधैव कुटुम्बकम् थीम पर आयोजित हुआ। एलजी वीके सक्सेना सराय काले खां के बनसेड़ा में डीडीए द्वारा आयोजित योग शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा, हमारे संतों ने योग की खोज की। यह स्वास्थ्य की कुंजी है। इसमें खर्च नहीं होता। सभी को इसे अपनाना चाहिए। विज्ञान भवन में आयोजित योग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया और पीयूष गोयल शामिल हुए।

वहीं, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यमुना नदी पर नाव में योग किया। उन्होंने सोनिया विहार में यमुना नदी के तट पर योगा ऑन वॉटर कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया और पानी पर योग किया। एमसीडी ने साउथ

दिल्ली, केशवपुरम और करोल बाग क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए। मेयर शैली ओबेरॉय ने सुभाष नगर सामुदायिक केंद्र, एमसीडी पश्चिम क्षेत्र में उप महापौर मो. आले इकबाल और आयुक्त ज्ञानेश भारती के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। एनडीएमसी ने 8 स्थानों पर योग शिविर लगाए। एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय नेहरू पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।

एम्स में योग केंद्र, मिलेट कैंटीन का उद्घाटन.. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्स में गो ग्रीन साइकिलिंग, मिलेट कैंटीन और योग केंद्र का उद्घाटन किया।

पंजाब केसरी DELHI
22 जून, 2023

बच्चों के साथ किया गया योगाभ्यास

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): विश्व योग दिवस के अवसर पर नन्हें कदम रोशनी की ओर फाउंडेशन द्वारा बुधवार को डीडीए पार्क में बच्चों के साथ योगाभ्यास किया गया। इसमें योग अध्यापक अरविन्द एनआईएस कोच एथलेटिक्स एंड फॉर्स स्पोर्ट्स क्लब के संथापक ने सभी बच्चों को योग के फायदे बताये। अरविंद जी ने बच्चों को योग में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों और उनके माता-पिता ने भी योग किया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ दैनिक भास्कर ----------DATED----------

नई दिल्ली, गुरुवार 22 जून, 2023

दिल्ली का विकास • 90% खर्च सरकार उठाएगी, बाकी इंडस्ट्रीज देगी

26 नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्र की किस्मत बदलेगी, 6 लाख नौकरियां जल्द

नॉन-कन्फर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास होगा

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

आप सरकार 26 नॉन-कन्फर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास करने जा रही है। दावा है कि ये विकसित हुए तो 6 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्योग विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि 26 नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया को कन्फर्मिंग एरिया बनाने से सभी क्षेत्रों का पुनर्विकास होगा।

उन्होंने बताया कि नॉन कंफर्मिंग एरिया में ले-आउट प्लान बनाने का 90 फीसद खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। 10 फीसद हिस्सा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से लेंगे। पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद ये कन्फर्मिंग एरिया घोषित होगा। नॉन-कन्फर्मिंग नोटिफाइड इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास कर विश्वस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रों में बदला जाएगा।

गांधी नगर बाजार ग्रैंड गारमेंट हब में विकसित होगा... वहीं, सीएम ने गांधी नगर बाजार को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए 'ग्रैंड गारमेंट हब' के रूप में विकसित करने की योजना की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए गांधी नगर बाजार का पुनर्विकास दो चरणों में होगा।

डीडीए दिल्ली की विकास गति के साथ नहीं चला

उद्योग विभाग के अफसरों ने डीडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन का सीमांकन करना डीडीए की जिम्मेदारी है। लेकिन जब रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल गतिविधियों का विस्तार हुआ था, तब डीडीए दिल्ली की विकास की गति के साथ नहीं चल पाया। ऐसे में रेजिडेंशियल कॉलोनियों की उपलब्धता नहीं होने से अनाधिकृत कॉलोनियां बनने लगीं।

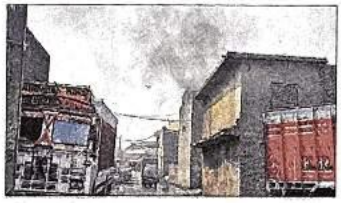

इन एरिया का होगा पुनर्विकास

आनंद पर्वत, शाहदरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, हस्तसाल पॉकेट-ए, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ी गांव, ख्याला, हस्तसाल पॉकेट-डी, शालीमार गांव, न्यू मंडोली, नवादा, रिठाला, स्वर्ण पार्क मुंडका, हैदरपुर, करावल नगर, डाबरी, बसई दारापुर, प्रह्लादपुर बांगर, मुंडका उद्योग नगर दक्षिण, फिरनी रोड मुंडका, रणहोला, नंगली सकरावती, टिकरी कलां।

नियमित क्लस्टर नहीं बने

दिल्ली में जमीन का इस्तेमाल मास्टर प्लान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए होने लगा, क्योंकि डीडीए की ओर से समय पर नियमित इंडस्ट्रीयल क्लस्टर नहीं बनाए गए। ऐसे में अवैध या नॉन कनफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया बनते गए। शहर के कई इलाकों में उद्यमियों को अपने व्यवसायों और कारखानों को चालू रखने के लिए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवासीय जमीन का इस्तेमाल करने को मजबूर होना पड़ा। वर्तमान में दिल्ली में कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं, जिसमें 70 फीसद से ज्यादा जमीन पर औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, जिन्हें नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया कहा जाता है।

री-डेवलपमेंट फेज-1

- व्यापारी की दिक्कत तुरंत दूर होगी।
- पेयजल, अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी।
- सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, सुरक्षा निगरानी प्रणाली स्थापित होगी
- स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट फर्नीचर फिर डिजाइन, होंगे। एलईडी से सूचना देंगे।

री-डेवलपमेंट फेज-2

- राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग कैंपेन।
- बाजार विशेषताएं सभी मीडिया माध्यमों पर दिखेंगी।
- वर्ल्ड क्लास इंफ्रा डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डेनसिटी पर लगाम कसेगी।
- व्यापार से जुड़े विकास को बढ़ावा।